फोन:-4103333, 2362400 फैक्स:-0141-2373513 वर्ष: 74 संख्या: 21 प्रभात जयपुर, मंगलवार 22 अगस्त, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

ARBiT

Jim Corbett had a 'large' respect for Sultana Daku

He was a serious embarrassment to the British Sakar, claimed Maharana Pratap's lineage, and modeled himself upon him.

Turning Waste Into Detergents

"It just screams along. It makes the alkylaromatics faster, & we can tune it to make the right-size molecules."

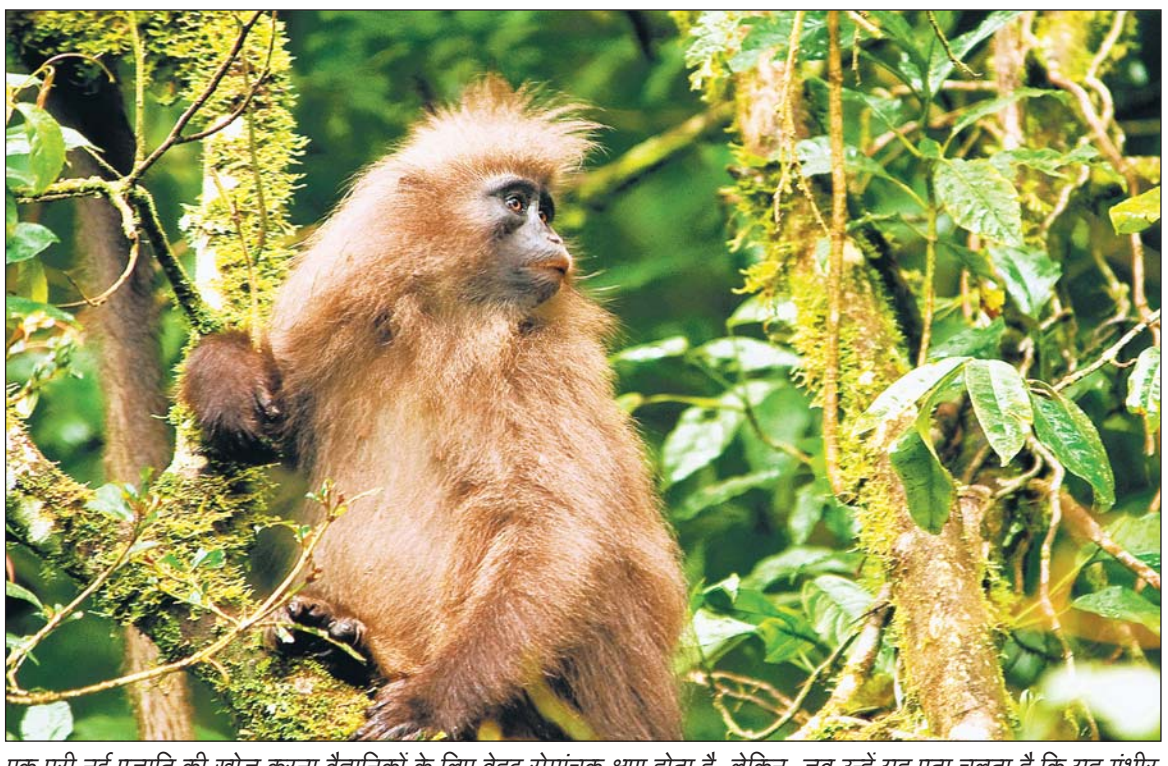

एक पूरी नई प्रजाति की खोज करना वैज्ञानिकों के लिए बेहद रोमांचक क्षण होता है, लेकिन, जब उन्हें यह पता चलता है कि यह गंभीर रुप से संकटग्रस्त है तो तकलीफ भी उतनी ही होती है। कीपुन्जी बंदरों को वर्ष 2003 में तंजानिया के कितूलो नैशनल पार्क के अंदर माउन्ट रुंगवे और लिविंगस्टोन माउन्टेन्स के जंगलों व ढलानों पर चिन्हित किया गया। स्थानीय लोगों ने वैज्ञानिकों को इस स्थान पर बंदर होने की सूचना दी थी। फिर उसी वर्ष मई में दक्षिणी हाइलैण्ड्स में बायोडायवर्सिटी सर्वे करते समय वैज्ञानिकों को, अजीब से दिखने वाले इस वानर की पहली झलक मिली और कई महीनों की मशक्कत के बाद वो इस जीव को ठीक से देख पाए। तब जाकर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टी की कि, सिर पर मुकुट जैसी तिकोनी कलगी, काले चेहरे और बबून जैसे थूथन वाले बंदर की यह प्रजाति पश्चिमी विज्ञान के लिए बिल्कुल नई है। जुलाई 2004 में तज़ानिया में ही उत्तर पूर्व की तरफ अन्य शोधकर्ताओं को भी एक नया प्राइमेट नज़र आया। सन् 2005 में दोनों टीमों ने मिलकर इस नई प्रजाति के बारे में जर्नल साइन्स में एक पेपर प्रकाशित किया तथा इसे कीपुन्जी नाम दिया और यह भी स्पष्ट किया कि यह एक नई प्रजाति है। माउन्ट रुंगवे और लिविंगस्टोन रेंज फॉरेस्ट, जहां कीपुन्जी वानर की 95 प्रतिशत आबादी बसती थी, नैशनल पार्क में नहीं था। यहाँ पर पेड़ काटना, और पेड़ काटकर कोयला बनाना तथा अवैध शिकार बहुत आम था। बाद में डब्ल्यु.सी.एस. के वैज्ञानिकों ने यहां संरक्षण की मुहिम चलाई। फिर, 2020 में हुए नए सर्वे में, जिसके निष्कर्ष हाल ही में इन्टर नैशनल जर्नल ऑफ प्राइमैटॉलजी में प्रकाशित हुए हैं, यह बात सामने आई कि इस क्षेत्र में अवैध कार्य 81 प्रतिशत तक घट गया है और कीपुन्जी की आबादी भी 65 प्रतिशत बढ़ गई है। तंजानिया सरकार ने कीपुंजी के आवास सहित तमाम क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया है और डब्ल्यु.सी.एस. भी यहां पूरी तरह से निगरानी कर रही है।

'2024 में एन.डी.ए. का प्रस्तावित वोट शेयर 42.60 प्रतिशत और इंडिया गठबंधन का 40.20 प्रतिशत'

टाइम्स नाओ के चुनावी सर्वेक्षण ने भाजपा की नींद उड़ाई, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन व विपक्षी गठबंधन में 2 प्रतिशत का ही अंतर है

- हाल ही में हुए दो चुनाव सर्वेक्षणों में विपक्षी गठबंधन, खासकर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा हुआ पाया गया है।
- मई माह में हुए सी.एस.डी.एस. सर्वे में भाजपा का वोट शेयर, 2019 के 37 प्रतिशत से बढ़ कर 39 प्रतिशत हो गया है, पर कांग्रेस का वोट शेयर 19 प्रतिशत से बढ़ कर 29 प्रतिशत हो गया है।
- सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस को दस प्रतिशत का यह उछाल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की बेहतर ब्रैंडिग तथा दक्षिण भारत व अल्पसंख्यकों में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ने और कर्नाटक व हिमाचल में जीत की वजह से मिला है।
- सूत्रों के अनुसार, इन नतीजों के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा। क्योंकि इसमें वो संवेदनशील तत्व या "शॉक एलिमैंट्स" शामिल नहीं हैं, जो देश की राजनैतिक दिशा बदल सकते हैं, जैसा वर्ष 2019 के चुनाव से पहले हुए पुलवामा और बालाकोट प्रकरणों ने राजनीति की दिशा को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया था।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। हाल ही में कराये गये दो चुनाव पूर्व सर्वे सत्तारूढ़ भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजाते प्रतीत हो रहे हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन तथा खासतौर से कांग्रेस, के लिए आशाजनक दिखाई दे रहे हैं। मई में हुये सी.एस.डी.एस. सर्वे के अनुसार, भाजपा 2024 में अपने 2019 के वोट शेयर, 37 प्रतिशत को बढ़ाकर 39 प्रतिशत तक पहुँचा देगी, वहीं 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर, उसके 2019 के वोट शेयर 19 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो जायेगा। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस के वोट शेयर में पिछले लोकसभा चुनावों के वोट शेयर की तुलना में 10 प्रतिशत का उछाल आयेगा। इस स्थिति के आंकलन के पीछे बहुत सारे कारणों का योगदान हैं- भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की बेहतर ब्रॉन्डिंग, दक्षिणी राज्यों तथा अल्पसंख्यक मतदाताओं में कांग्रेस की बढ़ी हुई स्वीकार्यता, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी विजय तथा मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुँचना।

दूसरा सर्वे जो, "ई.टी.जी. रिसर्च एंड टाइम्स नाउ" द्वारा विपक्षी गठबंधन में एन.डी.ए. का वोट शेयर 42.60 प्रतिशत, जबकि इंडिया का वोट शेयर 40.20 प्रतिशत रह सकता है तथा इस प्रकार, दोनों के वोट शेयर में केवल 2.4 प्रतिशत का अन्तर है। इन आँकड़ों में, बीजू जनता दल तथा वाई.एस.आर. सी.पी. के वोट शेयर को एन.डी.ए. के वोट शेयर में शामिल नहीं किया गया है वहीं बी.आर.एस. का वोट शेयर भी इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं है। जहाँ बीजू जनता दल तथा वाई.एस.आर.सी.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही तारीख को क्यों नहीं हो सकते?'

हाई कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान से 24 अगस्त तक इस सवाल का जवाब मांगा

- हाई कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान से कहा है कि, सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ कराने के संबंध में व्यवहारिक समाधान पेश करें, क्योंकि "वन बार-वन वोट" का सिद्धांत तभी लागू हो सकता है, जब सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ हों।
- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने ये मौखिक निर्देश 28 अगस्त को जयपुर में होने वाले द बार एसोसिएशन चुनाव में शपथ पत्र मांगने से जुड़े मामले में नरेन्द्र सिंह व अन्य की संयुक्त अपील की सुनवाई के दौरान दिए।

जयपुर, 21 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान (बी.सी.आर.) से पूछा है कि, प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव एक ही तारीख को क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? अदालत ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान से कहा है कि, वह एक ही समय सभी एसोसिएशन के चुनाव कराने के संबंध में व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करे और अपना जवाब 24 अगस्त तक पेश करे।

अदालत का कहना था कि, "वन बार-वन वोट" के कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब अलग-अलग एसोसिएशन के एक साथ चुनाव हों। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, अदालत भविष्य में सभी एसोसिएशन के चुनाव एक साथ करवा पाये तभी फर्जी एफिडेविट दायर करने और वोटर लिस्ट में अपात्र लोगों को जुड़वाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। परंतु अदालत ने कहा कि, वो 24 तारीख को ही यह फैसला लेगी कि इस वर्ष हो चुके और होने वाले एसोसिएशन के चुनाव एक साथ ही कराने हैं या नहीं। अब चर्चा यह है कि, इस वर्ष एसोसिएशनस के जो चुनाव हो चुके हैं उनको भी रद्द किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस (सी.जे.) ए.जी. मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश, द बार एसोसिएशन, जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले चुनाव में शपथ पत्र मांगने से जुड़े मामले में नरेन्द्र सिंह व अन्य की संयुक्त अपील पर दिए।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने द बार एसोसिएशन के चुनाव पर कहा कि, ये कैसा चुनाव है, जिसमें कोई समय सारिणी ही तय नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे, अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि इस चुनाव में नामांकन की तारीख के बाद मतदाता सूची तय हो रही है। उन्होंने बताया कि, नामांकन की सूची की तारीख 11 अगस्त को समाप्त हो चुकी थी परंतु वोटर लिस्ट 21 तारीख को फाइनल की गई है। उन्होंने कहा कि, उम्मीदवारों का वोटर लिस्ट में नाम भी बाद में जोड़ा गया है और कई तो अभी भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि, एक उम्मीदवार को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गृह मंत्रालय सर्वाधिक भ्रष्ट?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। दिल्ली कांग्रेस के नेता देवेन्द्र यादव ने "सैंट्रल विजिलैंस आयोग (सी.वी.सी.) की वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा है कि क्या अमित शाह का गृह मंत्रालय सर्वाधिक भ्रष्ट है?

- दिल्ली कांग्रेस के नेता देवेन्द्र यादव ने सी.वी.सी. की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों में भ्रष्टाचार की 1.15 लाख शिकायतें मिली हैं, इनमें से 46, 643 शिकायतें अकेले अमित शाह के गृह मंत्रालय की हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सर्वाधिक शिकायतें गृह मंत्रालय के बारे में मिली है। सी.वी.सी. रिपोर्ट कहती है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों व उनके अफसरों के खिलाफ 1, 15, 203

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका क्यों नहीं जा रहे हैं?

क्या पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का डर है

- इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ "वॉर क्राइम" के मामले में वारंट जारी कर रखा है। दक्षिण अफ्रीका इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्रीमैंट में शामिल है और अगर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका में कदम रखा तो वहां के राष्ट्रपति उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
- इसलिए यह समाधान निकाला गया है कि, पुतिन ब्रिक्स शिखर वार्ता को "वर्चुअली" संबोधित करेंगे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। रूस कैसी बुरी स्थिति में पहुँच गया है। जो रूस कभी, अमेरिका की टक्कर में, दूसरी इकलौती सुपर पावर था, आज उसी रूस के राष्टपति व्लादिमिर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं के सम्मेलन में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं।

और इस स्थिति के कारण हैं, खुद व्लादिमिर पुतिन। वे अपने साथ अपने देश को भी घसीट ले गये हैं तथा इतिहास के एक अप्रासंगिक दृश्य का शिकार बन के रह गये हैं। पुतिन ने उस रूस का स्वप्न देखा था, जो कुछ समय पूर्व, पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था।

उस पुराने और भुला दिये गये अतीत को हासिल करने की कोशिश में, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था ताकि उस देश को 21वीं सदी के रशियन एम्पायर में शामिल किया जा सके, मानो, उनका देश प्रबंध-क्षमता के हिसाब से पहले से ही बड़ा नहीं था। ज्ञातव्य है कि रूस का विस्तार ग्यारह टाइम-ज़ोन्स में है। पुतिन उसे और विशाल देखना चाहते थे और यूक्रेन को तो वे तत्काल ही अपने देश का हिस्सा बनाना चाहते थे।

जैसा कि लोग कहते हैं। तब से सब कुछ इतिहास बन कर रह गया। पुतिन विश्व समुदाय से अलग-थलग कर दिये गये और अब वे बिल्कुल अकेले पड़ गये हैं तथा कूटनीतिक जुड़ाव के लिये, अब उनके पास गिने-चूने विकल्प ही बचे हैं, और वे भी कम होते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा की कि पुतिन और खुद उन्होंने परस्पर सहमति जताई है कि पुतिन शिखरवार्ता में शामिल नहीं होंगे और वार्ता को "वर्चुअली" संबोधित करेंगे। पुतिन की अनुपस्थिति के पीछे कारण है इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा उनका "इनडिक्टमैंट (अभ्यारोपण)।

दक्षिण अफ्रीका भी इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्रीमैंट का हस्ताक्षरकर्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्यागी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। कर्नाटक की अब अपनी शिक्षा नीति होगी, यह घोषणा की है राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने। उन्होंने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्यागने का फैसला कर लिया है जिसे वर्ष 2021 में अपनाया गया था।

- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की कि, अगले शिक्षा सत्र से कर्नाटक में राज्य शिक्षा नीति लागू की जाएगी।

कर्नाटक पहला राज्य था जिसने देश की शिक्षा नीति को स्वीकार किया था। तब राज्य में भाजपा सरकार थी जो एच.डी. कुमारास्वामी की सरकार गिराकर सत्ता में आई थी।

राज्य में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को त्यागने का निर्णय महत्वपूर्ण है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब कांग्रेस कर्नाटक में "ऑपरेशन हस्त" शुरू करेगी, भाजपा विधायकों को तोड़ने के लिए

ये वो विधायक हैं, जिन्हें भाजपा ने 2019 में "ऑपरेशन कमल" अभियान से तोड़ा था और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी

- इस "ऑपरेशन हस्त" के सूत्रधार राज्य के उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डी.के. शिवकुमार हैं।
- कांग्रेस ने इसे अपने ही विधायकों की घर वापसी की संज्ञा दी है। कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा को करारी मात देने के लिए यह अभियान शुरू किया है, क्योंकि ये विधायक 12 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं।
- भाजपा पूरी कोशिश में है कि, इन विधायकों को अपने पास रख पाए, इसके लिए बी.एस. येद्दियुरप्पा को भी मैदान में उतारे जाने की तैयारी है।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। ऐसा नहीं कि केवल भाजपा ही विपक्षी सरकार को गिराने के लिये या अपने संख्या बल में वृद्धि करने के लिये अन्य पार्टियों के विधायकों को तोड़ती हो, कांग्रेस भी उसके साथ वैसा ही सुलूक कर सकती है। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा अब इस संभावना की तह में पहुंचने में लग गई है कि उसके कुछ नये विधायक अपनी मूल पार्टी में "घर वापसी" की ओर बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस के निशाने पर उसके वे पूर्व सदस्य हैं जो साढ़े चार साल पहले एच.डी. कुमारास्वामी सरकार को गिराने के लिये भाजपा में चले गये थे। भाजपा के विधायकों की "शॉपिंग" का मानस बनने का कांग्रेस का कारण यह नहीं है कि उसे विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये नये सदस्यों की जरूरत है क्योंकि उसके पास पहले ही अच्छा-खासा बहुमत है। दरअसल वह तो कर्नाटक में अपनी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, जहां पिछले आम चुनावों में भाजपा ने इकतरफा जीत हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस केवल उन्हीं भाजपा नेताओं को निशाना नहीं बना रही, जो पहले कांग्रेस में थे, वह जनता दल (सेकुलर) के कुछ विधायकों को भी अपनी ओर खींच रही है।

कर्नाटक के राजनैतिक हल्कों में ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि, जनता दल (एस)-कांग्रेस सरकार को गिराने वाले कांग्रेस के कुछ पूर्व बागी घर वापसी के लिये राजी किये जा रहे हैं। इस ऑपरेशन "हस्त" के संचालक के पी.सी.सी. अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हैं। अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ भी उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं तथा भाजपा के कुछ असंतुष्टों तथा जनता दल (एस) विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी हैं।

जिन प्रमुख हस्तियों के द्वारा घर वापसी किये जाने की उम्मीद है, उनमें भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री एस.टी. सोमशेखर भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया से भेंट की थी। वे उन 14 पूर्व कांग्रेसी विधायकों में से हैं, जो 2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे तथा एच.डी. कुमारास्वामी सरकार गिर गई थी।

जनता दल (एस) नेता अयानूर मंजूनाथ, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गये तथा इसके बाद फिर जे.डी. (एस) में पहुंच गये, भी डी.के. शिवकुमार से मिल चुके हैं तथा उनके जल्दी ही कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहें हैं। लेकिन कांग्रेस में मंजूनाथ की वापसी का विरोध भी हो रहा है। भाजपा नेता सी.टी. रवि ने भाजपा विधायकों की चोरी की अनुमानित कोशिश की निंदा की है।

पूर्व कांग्रेसी विधायकों की घर वापसी से संबंधित अफवाहों की आग में घी डालते हुए, शिवकुमार ने कहा, "हमें संख्या बल के लिये किसी की जरूरत नहीं है लेकिन में लोगों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिहार कास्ट सर्वे पर केन्द्र 7 दिन में जवाब दे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उन याचिकाकर्ताओं से कह दिया, जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बिहार सरकार को जातिगत सर्वे को जारी रखने के लिये कह दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस कवायद पर तब तक

- कोर्ट ने कहा, जब तक कोई मामला नहीं बनता तब तक बिहार कास्ट सर्वे पर रोक नहीं लगायी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक और मौका देते हुए 7 दिन का समय दिया, बिहार कास्ट सर्वे के विरोध में अपना पक्ष रखने के लिये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)